Financial Sector Reforms

Santosh Kumar Lal

Meaning

Financial sector reforms refer to the measures taken by the government and regulatory institutions to make the financial system more efficient, transparent, competitive, stable, and inclusive. These reforms cover banking, insurance, capital markets, pensions, and other financial institutions.

Major Objectives

- Improve the efficiency and stability of financial institutions.
- Promote competition and reduce excessive government control.
- Mobilize savings and channel them into productive investment.
- Strengthen regulation and supervision.
- Increase financial inclusion and access to credit.
- Develop capital markets and modernize financial infrastructure.

Major Financial Sector Reforms in India

- Banking-sector reforms: Introduction of prudential norms relating to capital adequacy, income recognition, asset classification and provisioning; greater operational autonomy and competition among banks.
- Liberalisation of interest rates: Interest rates were gradually deregulated to allow market forces to play a greater role.
- Capital-market reforms: Strengthening of Securities and Exchange Board of India (SEBI), modernization of stock exchanges, electronic trading and improved investor protection.
- Insurance-sector reforms: Opening the insurance sector to private participation and strengthening regulatory supervision through Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).
- Pension reforms: Development of a regulated pension system and expansion of market-linked pension products.
- Financial inclusion: Expansion of banking services, digital payments, basic bank accounts and credit facilities to underserved sections.
- Insolvency reforms: The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 created a time-bound framework for resolving insolvency and improving recovery of stressed assets.
- Digital financial reforms: Rapid adoption of UPI, mobile banking, Aadhaar-enabled services and other digital-payment infrastructure has transformed financial access.

Significance

Financial-sector reforms have helped India move from a highly regulated financial system toward a more market-oriented and technology-driven system. They have improved transparency, competition, access to finance and the resilience of financial institutions.

Challenges

- Non-performing assets (NPAs) and stressed assets.
- Cybersecurity and digital fraud.
- Financial illiteracy.
- Unequal access to formal finance.
- Regulatory coordination among different institutions.
- Balancing financial innovation with financial stability.

Conclusion

Financial-sector reforms are essential for sustainable economic growth. India needs to continue strengthening regulation, improving governance, expanding financial inclusion and adopting technology while ensuring financial stability and consumer protection.

अर्थ

वित्तीय क्षेत्र सुधार से आशय उन नीतिगत एवं संस्थागत उपायों से है, जिनके द्वारा बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, पेंशन तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को अधिक दक्ष, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, स्थिर और समावेशी बनाया जाता है।

मुख्य उद्देश्य:

- वित्तीय संस्थाओं की दक्षता एवं स्थिरता बढ़ाना।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा अनावश्यक सरकारी नियंत्रण कम करना।
- बचत को उत्पादक निवेश में परिवर्तित करना।
- वित्तीय नियमन और निगरानी को मजबूत करना।
- वित्तीय समावेशन तथा ऋण की उपलब्धता बढ़ाना।
- पूंजी बाजार का विकास एवं वित्तीय अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना।

भारत में प्रमुख वित्तीय क्षेत्र सुधार

- बैंकिंग सुधार: पूंजी पर्याप्तता, आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान जैसे विवेकपूर्ण मानदंड लागू किए गए। बैंकों की कार्यात्मक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया।
- ब्याज दरों का उदारीकरण: ब्याज दरों को धीरे-धीरे नियंत्रणमुक्त किया गया ताकि बाजार शक्तियों की भूमिका बढ़ सके।
- पूंजी बाजार सुधार: Securities and Exchange Board of India (SEBI) को मजबूत किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, निवेशक संरक्षण और पारदर्शिता में सुधार किया गया।
- बीमा क्षेत्र सुधार: निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई गई और Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) के माध्यम से नियामकीय व्यवस्था को मजबूत किया गया।
- पेंशन सुधार: संगठित एवं विनियमित पेंशन व्यवस्था का विस्तार किया गया।
- वित्तीय समावेशन: बैंक खाते, डिजिटल भुगतान, ग्रामीण बैंकिंग तथा कमजोर वर्गों के लिए ऋण सुविधाओं का विस्तार हुआ।
- दिवाला सुधार: Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 के माध्यम से दिवाला समाधान के लिए समयबद्ध व्यवस्था विकसित की गई।
- डिजिटल वित्तीय सुधार: UPI, मोबाइल बैंकिंग तथा अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने वित्तीय सेवाओं की पहुंच और उपयोग में व्यापक परिवर्तन किया।

महत्व

वित्तीय क्षेत्र सुधारों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को अधिक बाजारोन्मुख, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे वित्तीय संस्थाओं की कार्यक्षमता, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय समावेशन और निवेश के अवसरों में वृद्धि हुई है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs)।
- साइबर अपराध एवं डिजिटल धोखाधड़ी।
- वित्तीय साक्षरता की कमी।
- ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की असमान पहुंच।
- विभिन्न नियामक संस्थाओं के बीच समन्वय।
- वित्तीय नवाचार और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन।

निष्कर्ष

वित्तीय क्षेत्र सुधार आर्थिक विकास की आधारशिला हैं। भारत के लिए आगे भी मजबूत नियमन, बेहतर बैंकिंग प्रशासन, वित्तीय समावेशन, डिजिटल नवाचार, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय स्थिरता पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।